

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून: दिनांक 01 मार्च, 2014.

विषय:- जनपद-देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पूर्व में प्रत्यावर्तित 868.08 हे० वन भूमि में से 768.1552 हे० वन भूमि सिंचाई विभाग के स्थान पर उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 8-172/86-एफ०सी० दिनांक 31-10-1986 के द्वारा लखवाड़-व्यासी बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु 868.08 हे० वन भूमि कतिपय शर्तों के तहत सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु विधिवत स्वीकृति निर्गत की गई थी। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या एल० 127/14-3-804/86 दिनांक 28-02-1990 के द्वारा उक्त परियोजना के निर्माण हेतु 868.08 हे० वन भूमि सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। तदोपरान्त उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 1596/1(2)/2008-04 (08)/17/2003 दिनांक 23-06-2008 के द्वारा लखवाड़-व्यासी जल विद्युत परियोजना को उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० को आवंटित किया गया। उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० द्वारा लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 768.1552 हे० वन भूमि की स्वीकृति सिंचाई विभाग के स्थान पर उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० के पक्ष में स्थानान्तरित करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसे भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रयोक्ता एजेन्सी में परिवर्तन करने हेतु प्रेषित किया गया। राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8-172/1986-एफ०सी० (पार्ट-1) दिनांक 31-01-2014 के द्वारा कतिपय शर्तों के तहत विधिवत स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण के पत्र संख्या: 1992/1जी-3902(दे०दून) दिनांक 06-02-2014 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल महोदय जनपद-देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु पूर्व में प्रत्यावर्तित 868.08 हे० वन भूमि में से 768.1552 हे० वन भूमि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० (UJVNL) को 30 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर दिये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न हो तो उस वन भूमि का विधिवत पुर्नवास कर वन विभाग वापस किया जायेगा, जिसकी सूचना भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को दी जायेगी।



3. प्रयोक्ता एजेन्सी के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में लीज अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
5. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जलीय जीवों विशेषकर मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास हेतु किसी विशेषज्ञ संस्था से योजना तैयार करायी जायेगी, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार पुनर्वास कार्य किये जायेंगे।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करायी गई कैट प्लान की धनराशि से वन विभाग द्वारा लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के जलसमेत क्षेत्र के समेकित उपचार हेतु अनुमोदित कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (CAT Plan) क्रियान्वित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद-ललितपुर के अन्तर्गत लखवाड़-व्यासी बहुददेशीय परियोजना हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि पूर्व में ही उत्तर प्रदेश वन विभाग को उपलब्ध करायी गई थी। प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार उक्त भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण तत्समय किया गया था।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करायी गई व तदर्थ कैम्पा को स्थानान्तरित एन0पी0वी0 की धनराशि से वन विभाग द्वारा समय-समय पर नियमानुसार ए0पी0ओ0 के अनुसार अपेक्षित कार्य सम्पन्न कराये जायेंगे।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा इस आशय की वचनबद्धता वन विभाग को दी जायेगी कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि की जाती है, तो उनके द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।
12. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर परियोजना के जलाशय के चारों ओर तथा परियोजना क्षेत्र में रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का 4 फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलरों द्वारा (फोर बियरिंग व बैक बियरिंग लेकर) सीमांकन किया जायेगा। व प्रत्येक पिलर पर पिलर संख्या, DGPS coordinates आदि आवश्यक सूचनायें अंकित की जायेंगी। उक्त सीमांकर कार्यों के अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी स्तर पर संधारित किये जायेंगे।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त की जायेंगी।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना क्षेत्र में खनन क्षेत्रों का वैज्ञानिक दृष्टि से पुनर्वास हेतु एक योजना तैयार की जायेगी, जिसे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा। खनन कार्यों हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवे का वैज्ञानिक/तकनीकी विधि से निस्तारण किया जायेगा। खनन क्षेत्रों व मक डिस्पोजल स्थलों के जैविक/अभियांत्रिक उपचार का कार्य वन विभाग द्वारा एक योजना तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित की जायेगी।



17. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का पातन/निस्तारण उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा। केवल अपरिहार्य एवं न्यूनतम पेड़ों का ही पातन किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के समीप वनों पर जैविक दबाव कम करने हेतु परियोजना निर्माण में कार्यरत श्रमिकों/अन्य कर्मियों को जलौनी लकड़ी/गैस/केरोसिन तेल आदि उपलब्ध कराया जायेगा। जलौनी लकड़ी की आपूर्ति हेतु यदि आवश्यक हो, तो परियोजना क्षेत्र में जलौनी लकड़ी का टाल स्थापित करने के लिए प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवश्यक भूमि व अन्य वांछित सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी।
19. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
20. परियोजना क्षेत्र में वन विभाग द्वारा स्थापित की जाने वाली पौधशालाओं, वृक्षारोपणों एवं आवासीय भवनों हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवश्यकतानुसार वन विभाग को निःशुल्क पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
22. प्रयोक्ता एजेन्सी अथवा उसके ठेकेदारों द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान विस्फोटकों का प्रयोग नियमानुसार किया जायेगा व इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किये गये मानकों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
23. प्रश्नगत वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर पर मूल्य (प्रीमियम) एवं वार्षिक लीज रेन्ट शासनादेश संख्या-156/7-1-2005-500(826)/2002 दिनांक 09-09-2005 के प्रस्तर 3.2.5 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आंकलित किया जायेगा तथा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि का मूल्य व लीज रेन्ट का भुगतान किये जाने के उपरान्त ही परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का कब्जा दिया जायेगा।
24. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग से विधीक्षित करवाया जायेगा व उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी व प्रयोक्ता एजेन्सी के मध्य निष्पादित किया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या:-198/7-जी०-सी०-89-3-98, दिनांक 19-6-89 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक "0070"-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01-न्याय प्रशासन-501-सेवायें और सेवा फीस-01 -की सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही" के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
25. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
26. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विधिवत स्वीकृति विधि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सिविल अपील संख्या 6736 ऑफ 2013 (स्पेशल लीव पिटीसन (सी) संख्या-362/2012) में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-08-2013 के दिये गये परामर्श के अनुसार निर्गत की गई है।
27. राज्य सरकार द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की समीक्षा हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जायेगा व उक्त समिति द्वारा समय-समय पर शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।



2- उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं०-104/26/प्र०स०-आ०व०ग्रा०वि० दि०-1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं०-110/26/प्र०स०-आ०व०ग्रा०वि० दि०-4-1-2001 एवं शासनादेश संख्या-156/7-1-2005-500(826)/2002 दिनांक 9-9-2005 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

3- लखवाड़-व्यासी बहुददेशीय परियोजना के निर्माण हेतु पूर्व में जारी शासनादेश संख्या एल० 127/14-3-804/ 86 दिनांक 28-02-1990 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

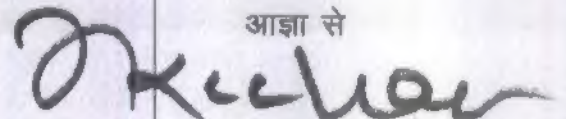
(राजेन्द्र कुमार)  
अपर सचिव।

संख्या- 2843 /7-1-2014-300(4234)/2013 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक यमुना वृत्त/शिवालिक वृत्त, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी/भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी एवं चकराता।
8. निदेशक (परियोजनायें), उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम, (UJVNL), महारानीबाग, उज्जवल भवन, देहरादून।
- ✓ 9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन.आई.सी. की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से



(राजेन्द्र कुमार)  
अपर सचिव।